निराधार आरंभ

लेखक- अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

4 मई, 2019

"भारत की महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती बाहरी नहीं है, बल्कि यह घरेलू सद्भाव और एकता के रखरखाव से संबंधित है।"

कई विश्लेषकों, विद्वानों और शोधकर्त्ताओं ने चाहे वो भारतीय हों या विदेशी, आजादी के बाद के सात दशक भी भारत में एक 'रणनीतिक संस्कृति' की अनुपस्थिति और इसके शासकों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की परिणामी अवहेलना को देखा है। ऐतिहासिक रूप से, भारत को फारसियों, यूनानियों, अरबियों, तुर्कों, अफगानों, मंगोलों और मुगलों द्वारा इसके उत्तर-पश्चिमी दर्रे पर और इसके तटों पर यूरोपीय लोगों द्वारा आक्रमणों का सामना करना पड़ा है।

हालांकि, हम इनमें से किसी भी आक्रमणकारी को पराजित करने में विफल रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक तथ्य यह है कि जो लोग भी आए, उन्हें भारत की समृद्ध संस्कृति ने आत्मसात कर लिया और वे 'भारतीय' बन गए। यूरोपीय समुद्री आक्रमणकारियों, जिनकी दिलचस्पी आत्मसात होने में नहीं थी, वे चार शताब्दियों तक केवल शोषण, लूट और साम्राज्य स्थापित करने के लिए रहे।

ऐतिहासिक रूप से, हमारी कमी, जिसमें आंतरिक एकता का अभाव, रणनीतिक सोच की कमी, योजना की अनुपस्थिति और तकनीकी पिछड़ापन शामिल है, ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए विदेशियों को सक्षम बनाया और हमें स्वतंत्रता से वंचित किया। ये सब तथ्य इस बात का सबूत हैं कि हमने इतिहास से अब तक सबक नहीं सीखा है क्योंकि भारतीय राजनीति चल रही आंतरिक विद्रोहियों और लगातार आतंकी हमलों के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के प्रति उदासीन बना हुआ है।

शायद ही, पिछले 72 वर्षों में, भारतीय संसद में रक्षा बजट पर चर्चा करने, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने या सरकार से रक्षा समीक्षा/सुरक्षा रणनीति की मांग के लिए आवाज उठाई गयी हो। न केवल संसद रक्षा पर अपनी स्वयं की स्थायी समिति की वार्षिक सिफारिशों को नजरअंदाज करती है, बल्कि कमेटी द्वारा भी जब कठोर तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है तब भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है।

1999 में कारगिल युद्ध ने राजनीतिक प्रतिष्ठान को दर्शाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत गलत हुआ है। जिसके बाद, एनडीए और यूपीए, दोनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा करने और सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूहों का गठन किया। हालांकि, दोनों निकायों की महत्वपूर्ण सिफारिशें, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की नौकरशाही की खाई में गायब हो गई और इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार सीमित अधर में लटक गये।

अगर हम 1999 के IC-814 अपहरण के साथ शुरूआत करें, तो हम पाएंगे कि इस सदी के शुरुआती वर्षों में भारत को लगातार कई संकटों का सामना करना पड़ा था। हर बार, देश बेतैयार और निरपवाद रूप से प्रतिक्रियाशील मोड में था। हालांकि, यह सब 29 सितंबर, 2016 को बदल गया, जब एनडीए सरकार ने एलओसी के पार आतंकी शिविरों पर दंडात्मक हमले करने के लिए विशेष बल तैनात किया। फरवरी, 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी शिविर पर किये गये हवाई हमले ने इस सरकार के दृढ़ संकल्प की फिर से पुष्टि की, जिसका साफ तौर पर कहना था कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमापार आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

देखा जाये, तो इन दृढ़ कार्यों ने अच्छी तरह से योग्य सार्वजनिक अनुमोदन प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी दो महत्वपूर्ण पहलुओं

को उजागर करने की आवश्यकता है। जिसमें पहला यह है कि जहाँ एक तरफ लंबे समय से लंबित सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरा श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के लिए पार्टी द्वारा इन अभियानों का इस्तेमाल बेढंग तरीके से करने से सेना को शर्मिंदा किया और इनकी उपलब्धियों को तुच्छ बनाया है।

दूसरा, सितंबर, 2016, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर मौका बन सकता था, उसे हमने खो दिया अर्थात् प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए संकेत देने के उद्देश्यों के साथ, जिसमें स्वयं की सेना को एक दिशा-निर्देश प्रदान करना था कि इस तरह के सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर कदम उठाया जाएगा और इससे राष्ट्रीय मनोबल और आत्मविश्वास में भी बढ़ोत्तरी होती।

भारत में जल्द ही एक नव-निर्वाचित सरकार होगी। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, सभी पार्टी के घोषणापत्र समान रूप से नीरस और अस्पष्ट हैं, जो इस आशंका की पुष्टि करता है कि सुरक्षा के बारे में हालिया मुद्दा केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा था।

भारत की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती बाहरी नहीं है, बल्कि घरेलू सद्भाव और एकता के रखरखाव से संबंधित है। इतिहास ऑस्ट्रो-हंगेरियन और ओटोमन साम्राज्यों के साथ-साथ सोवियत और यूगोस्लाव गणराज्य जैसे उदाहरणों से परिपूर्ण है, जिन्होंने बहु-धार्मिक और बहु-जातीय आबादी को राष्ट्र-राज्यों में बनाने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः विफल और खंडित हो गए। प्रत्येक प्रमुख ध र्म का प्रतिनिधित्व करते हुए और हजारों जातीय समूहों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए, भारत एक साहसी लेकिन नाजुक प्रयोग कर रहा है, किन्तु सभी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता अधिकारों से सख्ती से जुड़े हुए हैं। एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद, हमारे राजनेताओं को इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या भारत धार्मिक प्रवृत्ति को राजनीतिक प्रवचन पर हावी होने दे सकता है।

हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय राज्य तब तक अपने आप को कभी भी सुरक्षित नहीं मान सकता, जब तक कि वह अपने प्रत्येक नागरिक के लिए भय से सुरक्षा तथा स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं देता। अधिकांश के लिए एक तथ्य अज्ञात है कि एक भारतीय सशस्त्र बल, जो वर्तमान में संरचित है, 'सर्व धर्म समभाव' का प्रतीक है।

भारत का आधा खाली शस्त्रागार और हथियारों के आयात पर भारी निर्भरता 'बढ़ती शक्ति' स्थिति के लिए अपने दावों का ही मजाक उड़ाते हैं। 'मेक इन इंडिया' एक प्रेरणादायक नारा है, जिसे 50 साल के विजन-कम-एक्शन प्लान (vision-cum&action plan) द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इसका कार्यान्वयन भारत के सैन्य-औद्योगिक परिसर की एक नई संरचना के साथ-साथ एक नए 'रक्षा उत्पादन और अधिग्रहण मंत्रालय' के निर्माण से होना चाहिए।

अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दोष भारत के सशस्त्र बलों के रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में निहित है, जिसे एक सामान्य नागरिक नौकरशाही द्वारा विशेष रूप से चलाया जाता है और सशस्त्र बलों को एक-दूसरे के साथ एकीकृत करने में यह विफल है। नतीजतन, भारत साइबर, परमाणु और अंतरिक्ष युद्ध के इस युग में प्रमुख सैन्य शक्तियों के बीच कमजोर है।

चीन के आसमान छूते रक्षा खर्च के बारे में मीडिया ने कई बार चिंता प्रकट की है। लेकिन हमारे राजनेताओं को जागृत रखने वाली दो चीजें जो है वो चीन की हाल ही में एकीकृत और आधुनिकीकरण वाली क्षेत्रीय सैन्य कमांड और दूरदर्शी व्हाइट पेपर्स हैं जिसे इसके रक्षा मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)

क्या है?

- सन् 1998 में जब भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र घोषित कर दिया, तब यह भी मुद्दा उठा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समग्रता में अध्ययन हेतु एक शीर्ष संस्था बनाई जाए।
- एक ऐसी संस्था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर अध्ययन करे और सरकार को भविष्य की रूपरेखा बनाने और नीति निर्धारण में सुझाव दे।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी संस्था बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके सदस्य थे कृष्ण चंद्र पंत, जसवंत सिंह और एयर कमोडोर जसजीत सिंह (सेवानिवृत्त)।
- दिसंबर, 1998 में इस समिति के सुझावों पर अमल करते हुए 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्' (National Security Council) का गठन किया गया।

संरचना

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तीन अंगों वाली परिषद् है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का पूरा काम-काज देखते हैं।
- इस परिषद् के तीनों अंग इस प्रकार हैं: सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (NSCS) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)

वर्तमान परिदृश्य

- केंद्र सरकार ने 08 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSC) की सहायता के लिए गठित रणनीतिक नीति समूह (SPG) को आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ पुनर्गठित किया है।
- रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की सहायता के साथ ही देश के सुरक्षा मामलों की दीर्घकालिक रणनीतिक समीक्षा समेत दूसरे कार्य करेगा।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् देश के सुरक्षा एवं रणनीतिक हितों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है। यह एक कार्यकारी सरकारी संस्था है।

गठन का उद्देश्य

- रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की नीति निर्माण में सहायता करने के साथ ही देश के सुरक्षा मामलों की दीर्घकालिक रणनीतिक समीक्षा करना है।

रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी)

- रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) का गठन अप्रैल, 1999 में किया गया था। एसपीजी का गठन बाहरी, आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (एनएससी) की मदद् के लिए किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले रणनीतिक नीति समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव किया करते थे, जिसमें 16 सदस्य होते थे, जबकि अब इसके सदस्य बढ़ाकर 18 कर दिए गए।
- जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट सचिव को इसका नया सदस्य नियुक्त किया गया है।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा LOC के पार आतंकी शिविरों पर दडांत्मक हमला करने के लिए विशेष बल तैनात किया गया था।
2. भारत का रक्षा बजट 2019-20 में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements-

1. In 2017, Indian government had deployed special force to take punitive action against the terrorist camp across LOC.
2. First time the defence budget of India crossed 3 lakh crore mark in 2019-20.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- "भारत की महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती बाहरी नहीं है, बल्कि यह घरेलू सद्भाव और एकता के रखरखाव से संबंधित है।" इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

Q. "The important security challenge of India is not external but it is related to domestic goodwill and maintanence of unity." Critically evaluate this statement. (250 Words)

प्रश्न:- वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त' क्यों आवश्यक है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Considering the present scenario, why the 'national security doctrine' is required? Discuss. (250 Words)

नोट : 3 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World Committed to Excellence